Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 12-05-2005

Participants : Suman Shri Ramji Lal

an>

Title: Need to increase honorarium of vocational teachers in the country.– Laid.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोठारी कमीशन की संस्तुति के आधार पर 1989 में देश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में+2 स्तर पर केन्द्र पुरोनिधानित रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा योजना लागू की थी जिसमें प्रवक्ता स्तर पर शिक्षकों को 15 सौं रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। र्वा 2003-04 तक तो शिक्षकों को यह मानदेय मिलता रहा है लेकिन इस र्वा 2004-05 के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना के प्रारंभ होने पर यह सुनिश्चित किया गया था कि 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार करेंगी, उत्तर प्रदेश में यह महत्वाकांक्षी योजना जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वरोजगार तथा ग्रामीण अंचल के गरीब छात्रों को तकनीकी शिक्षा उलब्ध कराना है, अभी निरंतर चल रही है लेकिन अफसोस है कि केन्द्र सरकार का अपेक्षित सहयोग राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर विनम्र आग्रह किए जाने के बावजूद इस साल शिक्षकों का मानदेय का बकाया 3 करोड 75 लाख रूपए की धनराशि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है। यह भी जानकारी मिली है कि भारत सरकार देश के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठयक्रम में कुछ संशोधन करना चाहती है। इस व्यावसायिक शिक्षा के काफी उपयोगी परिणाम निकले हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इन व्यावसायिक शिक्षकों को मिलने वाले अव्यावहारिक मानदेय में संशोधन कर इस धनराशि को बढ़ाया जाये। भारत सरकार इस साल की उत्तर प्रदेश को मिलने वाले धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करे तथा इस व्यावसायिक पाठयक्रम में किसी प्रकार के संशोधन के बाद यदि सेवा शर्तो में कोइ परिवर्तन होता है तो सबसे पहले 1989 से सेवारत इन व्यावसायिक शिक्षकों को समायोजित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।